(b) whether it is also a fact that Government are thinking of making statutory provisions by which the amployers of the firms are compiled to provide the above mentioned facilities ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA) : (a) and (b). There is no present proposal for extending the existing area of lagislative compulsion.

(c) Does not arise.

Development of Agriculture in Mysore State

*96. SHRI N. SHIVAPPA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to State :

(a) The amount proposed to be spent on the development of agriculture out of the proposed total allocation made in the Fourth Plan of Mysore State;

(b) whether Government propose to formulate any special scheme for the development of agriculture in Mysore State and so that self-sufficiency may be achieved ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASRHIB SHINDE) : (a) According to the Fourth Five Plan, (1969-74) Draft, published by the Planning Commission, the total allocation for the Fourth Plan of the Mysore State was Rs. 327.10 crores out of which Rs. 76.75 crores were for agricultural programmes. The final Fourth Five Year Plan is, however, under consideration.

(b) and (c). A new strategy of Agricultural Development has been adopted since 1966-67 in all the States including Mysore. The main elements of the new strategy are : cultivation of high yielding varieties of seeds of foodgrains, multiple cropping, minor irrigation for intensive cultivation, organised provision of inputs like fertilizers and pesticides, timely and liberal credit facilities including institutional finance, ensuring incentive prices, farmers education and training and intensification of research.

Supply of Rice to Kerala

*97. SHRI VASUDEVAN NAIR :
SHRI K. ANIRUDHAN :
SHRI P. GOPALAN :
SHRI C. K. CHAKRAPANI :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state ;

(a) the quantity of rice supplied to Kerala by the Union Government in 1969 ; and

(b) the prospect of increasing the supplies to Kerala in 1970, whether it will be sufficient to keep up the present quantum of 160 grams of ration to the cardholders ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) The quantity of rice supplied from the Food Corporation of India's godowns in Kerala to the fair price shops and other nominees of the State Government during 1969 was 7.61 lakh tonnes.

(b) The present quantum of rice ration in Kerala is 120 grams per adult per day. Supplies of rice from the Central pool are expected to be sufficient to maintain distribution at this rate and to increase it to 160 grams per adult per day during the lean season.

सुपर बाजार, नई दिल्ली द्वारा किराये का भुगतान न किया जाना

* 98. श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री सामिनाथन् :
श्री सेझियान :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार, नई दिल्ली बहुत घाटे में चल रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने किराये का भुगतान न किये जाने के आधार पर सुपर बाजार को वहां से हटाये जाने के लिए सुपर बाजार के प्रबन्धक को नोटिस दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि घाटा होने का कारण कुप्रबन्ध है और क्या इस बारे में दिल्ली प्रशासन से कोई विरोधी पत्र प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो कितना घाटा हुआ ; और

(ङ) सुपर बाजार खोलने का उद्देश्य कहाँ तक पूरा हुआ है और यह सुनिश्चित करने के लिए की सुपर बाजार एक घाटे वाला संगठन न बन जाये, क्या उपाय करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डा. एरिंग) : (क) इसे अपने कार्यचालन के प्रथम तीन वर्षों में हानि हुई ।

(ख) जी, हां ।

(ग) हानि के मुख्य कारण ये हैं—प्रथम वर्ष में कारोबार बढाने संबन्धी अधिक व्यय, कनाट सर्कस में इमारत का अधिक किराया, प्रशासनिक तथा परिचालन संबन्धी अधिक व्यय तथा स्टाक में अधिक कमियां और वस्तुओं का अनधिकृत रूप से बाहर जाना । दिल्ली प्रशासन से ऐसा कोई प्रतिवाद प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु इनमें सुधार लाने के प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन तथा भारत सरकार द्वारा ध्यान दिया जाता रहा है ।

(घ) जून, 1969 के अन्त तक लगभग 40 लाख रुपए ।

(ङ) सुपर बाजार की स्थापना रुपये के अवमूल्यन के समय उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाने के उपायों के अंग के रूप में जुलाई, 1969 में की गई थी । इसने प्रारम्भ में उचित मूल्यों पर वस्तुएँ बेचकर और उचित व्यापारिक प्रथाएं अपनाकर उपभोक्ता बस्तुओं के मूल्यों की प्रवृत्ति पर स्वस्थ प्रभाव डाला डाला था यह वर्तमान परिस्थितियों में भी अपने कार्यचालन में और सुधार करके एक प्रभाव-शाली भूमिका अदा कर सकता है । सुपर बाजार के मैनेजमेन्ट द्वारा, सुधरे व्यापारिक तथा प्रशासनिक तरीकों को अपनाकर, वस्तुओं के अनधिकृत रूप से बाहर ले जाने तथा स्टाक में होने वाली कमी को रोक कर, व्यय में किफायत करके तथा बिक्री और आय के दूसरे साधनों को बढ़ाकर, हानि को कम करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

Nationalisation of Sugar Industry

*99. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA :
SHRI JAGESHWAR MISRA :
SHRI RAM SEWAK YADAV :
SHRI SRADHAKAR SUPAKAR :
SHRI RAMKISHAN GUPTA :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether any scheme has been drawn up to nationalise the sugar industry in the entire country on some uniform basis ;

(b) if so, the outlines and complete details thereof; and

(c) if not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.